भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1912
11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

अपतटीय खनन

1912. डॉ. शशि थरूर:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि केरल में निर्माण रेत के अपतटीय खनन परिचालन केरल के मछुआरों के आर्थिक अस्तित्व को सीधे कैसे प्रभावित करेंगे, जो अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक मछली पकड़ने पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मछली प्रजनन स्थलों और उनके प्रवासी पैटर्न पर अपतटीय खनन गतिविधियों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (घ) खान मंत्रालय, भारत सरकार ने अपतट क्षेत्र खनिज एवं विकास अधिनियम, 2002 पारित किया, जो 2010 में प्रभावी हुआ। आज तक प्रादेशिक जल (टेरिटोरियल वाटर्स), एक्सक्लूसिव इकोनोमिक ज़ोन (ईईज़ेड) कॉन्टिनेन्टल शेल्फ आदि सहित अपतटीय क्षेत्रों में कभी भी कोई खनन नहीं हुआ है। इसलिए केरल तट पर अपतटीय खनन के प्रभाव का आकलन करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय राज्यों और द्वीपों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए 106 तटीय और समुद्री स्थलों की पहचान की गई है और उन्हें महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों / कोस्टल एंड मरीन बायोडाईवरसिटी एरियास (आईसीएमबीए) के रूप में प्राथमिकता दी गई है। खान मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि अपतटीय ब्लॉकों में ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, परिचालन अधिकार के निष्पादन से पहले, बोलीदाताओं को उत्पादन संचालन के संबंध में लागू किए गए कानूनों के तहत सभी सहमतियां, अनुमोदन,
परमिट, अनापत्तियां प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, उत्पादन योजना के अनुसार ही कोई भी उत्पादन कार्य किया जाएगा। उत्पादन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ एक पर्यावरण प्रबंधन योजना भी शामिल है, जिसमें आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन उपायों का उल्लेख है। केरल तट से दूर तीन अपतटीय रेत ब्लॉक बेसलाईन से 12 नौटिकल माईल्स से आगे हैं और मछली पकड़ने के मैदानों की सुरक्षा और मछुआरों की आजीविका के पहलुओं से संबंधित मुद्दों को उत्पादन योजना तैयार करते समय और पर्यावरण प्रबंधन योजना में भी उचित रूप से शामिल किया जाना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को केरल के तट पर अपतटीय खनन गतिविधियों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए नामित किया गया है।

*****